

प्रेषक,

आलोक कुमार वर्मा,
सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निबन्धक,
उत्तराखण्ड लोक सेवा अधिकरण,
निकट आई0टी0आई0 निरंजनपुर,
सहारनपुर रोड़, देहरादून।

न्याय अनुभाग-1

देहरादून: दिनांक 08 फरवरी, 2017

विषय- उत्तराखण्ड लोक सेवा अधिकरण, देहरादून में संयुक्त निबन्धक (सिविल जज, सीनियर डिवीजन वेतनमान में) के पद की निरन्तरता बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में।


महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0-06/उ0लो0से0अधि0/प्रशा0-IV दिनांक 09.01.2017 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश सं0-168/XXXVI/2011-326/2011 दिनांक 01.09.2011 द्वारा पुर्नजीवित/सृजित संयुक्त निबन्धक का 01 पद की निरन्तरता वर्तमान शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन, यदि वे बिना पूर्व सूचना के पहले ही समाप्त न कर दिये जाय, दिनांक 01.03.2017 से 28.02.2018 तक बढ़ाये जाने की श्री राज्यपाल, सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- उक्त पर होने वाला व्यय आगामी वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय व्ययक के अनुदान संख्या-04 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2014-न्याय प्रशासन-00-आयोजनेत्तर-800-अन्य व्यय-04-लोक सेवा अधिकरण- 00" के अन्तर्गत सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामें डाला जायेगा।

3- यह आदेश उत्तर प्रदेश शासन के वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के कार्यालय ज्ञाप सं0-ए-2-2574/ दस-98-24(8)92 लखनऊ दिनांक 02 दिसम्बर, 1998 सपठित ए-1270/76-दस दिनांक 20.07.1968 एवं कार्यालय ज्ञाप सं0-ए-2-877/दस-92-24(8)/92 दिनांक 07.11.1992 (यथा उत्तराखण्ड राज्य में प्रवृत्त) द्वारा प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधानित किये गये अधिकारों के अन्तर्गत प्रसारित किये जा रहे हैं।

भवदीय,



(आलोक कुमार वर्मा)
सचिव

संख्या- 38 /XXXVI(1) / 2017-326 / 2001 T.C. तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड, ओबरॉय भवन, माजरा, देहरादून।
2. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
3. वित्त अनुभाग-5/कार्मिक अनुभाग/एन0आई0सी0/गार्ड फाईल।

आज्ञा से,


(महेश चन्द्र कौशिका)
अपर सचिव